

## श्री चुनीभाई वैद्य

रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता - 2010

इस पुरस्कार के प्रेरक परम आदरणीय श्री जमनालालजी गांधी-विनोबा का बहुत आदर करते थे जिनका आदर्श था शासन-मुक्त समाज.

विनोबाजी ने सामाजिक कार्य के दो प्रकार गिनाये- राहत कार्य और क्रांतिकारी कार्य. उन्होंने हिदायत दी थी कि समाजव्यवस्था - परिवर्तन का क्रांतिकार्य करना हो तो संस्था मत बनाओ. क्यों ? संस्था बनाओगे तो आप को सत्ता और धन के आश्रित बनना पड़ेगा, मुक्त रूप से बोल या चल नहीं सकोगे. मैंने उनके बताये हुए रास्ते पर चलने की यथाशक्ति कोशिश की, संस्था नहीं बनाई इसलिये न बना मकान, न रख सका कोई विशेष स्टाफ; आंखों में दिखाई दे वैसा कुछ भी नहीं.

मैंने गुप्त बांध बनाये जिसमें न लोहा, न लकड़, न ईंट, न पत्थर, न चूना, न सीमेन्ट. मिट्टी तक इस्तेमाल नहीं की. फिर भी उन के पानी से हजारों बीधा भूमि सिंचित की जाती है. सरकार की किसी प्रकार की देखल के बिना किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पानी उठाते हैं. पूर्ण रूपेण सरकार -मुक्त व्यवस्था.

सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा तो कर के सरकार से करीब ७००० भूमिहीनों को बीस हजार एकड़ परती भूमि दिलवाई. हम लोगों ने कहा यह भूमि अपर्याप्त है. अधिक दीजिये. सरकार ने कहा उसके पास भूमि नहीं है. उधर सरकार अदानी, अंबानी, अेस्सार, मोलारिस, केमटेक आदि उद्योगपतियों को पांच हजार, दस हजार, पंद्रह हजार एकड़ भूमि पानी के मोल दे रही है. अतः मुझको सरकार से भूमि मांगना अपमानजनक लगा. मैंने बुनियादी सवाल लेकर आंदोलन आरंभ किया - प्राकृतिक संसाधन - जल, जंगल, जमीन, नदी-समंदर, खनिज आदि की मालकीयत किस की - सरकार की या समाज की ? एक सूत्र दिया - 'गांव की भूमि गांव की, नहीं किसी सरकार की.' आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है. इसमें जनता का प्रशिक्षण होता है. और परिणाम दूरगामी होगा. भूमि का प्रबंधन सरकार के हाथों से निकल कर ग्रामसभा के हाथ में जायेगा. वैसा ही सारे प्राकृतिक साधनों के बारे में होगा. यह सारा हमको सहभागी लोकतंत्र -विकेन्द्रित शासन - व्यवस्था, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था आदि की तरफ ले जायेगा. शासन न्यूनतम करने की दिशा खुलेगी.

आज की सरकारों की गलत अर्थनीति को देखते हुए हम कार्यकर्ताओं की चाह है कि यह संदेश पूरे देश में प्रसारित हो - 'गांव की भूमि गांव की, नहीं किसी सरकार की', 'प्राकृतिक संसाधन की मालकीयत समाज की', 'शासन-मुक्त समाज!'